राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 7831/2023

राजेश कुमार पुत्र विश्वनाथ प्रसाद, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम मुसैला, पुलिस स्टेशन मोहनपुर, जिला गया (बिहार)
(जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ, एनसीबी के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री बी.आर. बिश्नोई
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री एम.आर. पारीक, विशेष पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

21/02/2024

1. वर्तमान जमानत आवेदन याचिकाकर्ता की ओर से सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर किया गया है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18 और 8/29 के तहत अपराध के लिए एनसीबी, जोधपुर की एफआईआर संख्या VIII[10]/03/NCB/JZU/2020 के संबंध में हिरासत में है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिकाकर्ता के कब्जे से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त व्यक्ति, जिनसे प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी की गई है, को पहले ही इस न्यायालय द्वारा जमानत पर बढ़ाया जा चुका है। वह प्रार्थना करते हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता 75% विकलांग है।

4. इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पुलिस स्टेशन डांगियावास में दर्ज केस संख्या 119/2022, एएसजेड, एनसीबी, अजमेर में दर्ज केस संख्या 1/2021 और एनसीबी, जोधपुर में दर्ज केस संख्या 9/2018 जैसे समान प्रकृति के मामलों में शामिल है और इसलिए, वह एक आदतन अपराधी है और राजस्थान राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की पिछली रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके फिर से उसी प्रकृति के मादक पदार्थों की तस्करी/अपराधों में शामिल होने की पूरी संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ (33 किलोग्राम अफीम) बरामद किया गया है।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने आगे कहा कि पहले के अवसरों पर, हालांकि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन इस न्यायालय के समक्ष दायर जमानत आवेदन को रद्द करने पर, उसे अनुमति दी गई थी और इस न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को तीस दिनों की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने समय पर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और अंततः दो साल की अवधि के बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा, तो प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की हिरासत ले ली, इसलिए, ऐसी स्थिति में, यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का लाभ दिया जाता है, तो उसके द्वारा इसका दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने यह भी कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला सह-आरोपी व्यक्तियों के मामले से स्पष्ट रूप से भिन्न है, जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया है, क्योंकि सह-आरोपी व्यक्तियों की रिहाई उनके द्वारा काटी गई हिरासत अवधि के आधार पर थी और निश्चित रूप से याचिकाकर्ता ने सह-आरोपी व्यक्तियों के बराबर हिरासत अवधि नहीं काटी है, जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। इसलिए, वह प्रार्थना करता है कि जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

7. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए सबमिशन पर विचार किया है और मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखा है।

8. निश्चित रूप से, वर्तमान मामले में, अफीम की एक बड़ी मात्रा यानी 33 किलोग्राम बरामद की गई है। याचिकाकर्ता के खिलाफ अफीम की आपूर्ति करने का आरोप है। याचिकाकर्ता राजस्थान राज्य में मादक पदार्थों के कारोबार के कम से कम तीन और मामलों में शामिल पाया गया है और उसके खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और उनकी सुनवाई ट्रायल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करके न्यायालयों द्वारा दी गई स्वतंत्रता का उसके द्वारा बार-बार समान प्रकृति के अपराधों में शामिल होकर घोर दुरुपयोग किया गया है। व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आधार हमेशा यह होता है कि वह उस अपराध में शामिल नहीं होगा या ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर संदेह है। याचिकाकर्ता का तीन मौकों पर समान प्रकृति के अपराधों में शामिल होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करके न्यायालयों द्वारा दी गई छूट का दुरुपयोग कर रहा है। याचिकाकर्ता के आचरण से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के ऐसे अपराधों में शामिल होने के कारण बड़े पैमाने पर समाज पीड़ित है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी: (2010) 14 एससीसी 496 के मामले में निम्नानुसार माना है:-

> “12. प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी: MANU/SC/0916/2010: (2010) 14 SCC 496 में, अभियुक्त को जमानत देने के उच्च न्यायालय के अधिकार में हस्तक्षेप करने की न्यायालय की भूमिका से निपटते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह देखा जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने इस विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और उस बिंदु पर निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन में सख्ती से किया है। न्यायालय ने कारकों को गिनाना शुरू किया:
>
> 9…… अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखने वाले कारक हैं:
>
> (i). क्या यह मानने का कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है;
>
> (ii). आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(iii). दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता

(iv). जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा;

(v). अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और रुतबा;

(vi) अपराध के दोहराए जाने की संभावना;

(vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; और

(viii) जमानत दिए जाने से न्याय के विफल होने का खतरा।"

10. याचिकाकर्ता का आचरण यह है कि जमानत रद्द होने के बावजूद उसने समय पर अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने के लिए पूरी मशीनरी लगानी पड़ी।

11. यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देता है कि यदि कोई व्यक्ति कई बार मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल रहा है, तो यह कहा जा सकता है कि वह आदतन अपराधी है। यह भी एक तथ्य है कि छोटे स्थानों/शहरों में मादक पदार्थों की उपलब्धता और बिक्री और वितरण दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे परिवारों में बहुत सारी अशांति पैदा हो रही है। युवा पीढ़ी मादक पदार्थों के सेवन से बर्बाद हो रही है और इसलिए, यह न्यायालय इस मामले में नरम रुख अपनाने के लिए राजी नहीं है।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, मामले की गंभीरता और याचिकाकर्ता के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और आरोप की प्रकृति और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, मैं इस स्तर पर याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूं।

13. तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा धारा 439 सीआरपीसी के तहत पेश की गई वर्तमान जमानत याचिका खारिज की जाती है।

(विनित कुमार माथुर**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।